allowed subject to payment by the party of other dues as also the legal charges incurred so far. The party deposited the other dues but not the legal expenses. As a result, the bank could not withdraw the suit till date, thus incurring further legal expenses.

'Non-serious' private power project proposals

1300. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appearing in the Hindu dated 22nd February, 1996 under the Caption "Most Private Power Project Proposals Non-Serious";

(b) if so, whether it is a fact that 75% of the power project proposals submitted by the Private Sector are "Non-serious";

(c) if so, in what manner Government propose to complete the task of grounding serious proposals; and

(d) the details of steps taken to complete the scrutiny of serious power sector proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) 106 expressions of interest exceeding Rs. 100 crores on the Memorandum of Understanding (MOU)/ Letter of Intent (LOI) etc. route have been received for setting up of power projects in the private sector, Central Electricity Authority has accorded 'in principle' clearance to 39 of the 48 proposals received. Techno-economic clearance of CEA has been accorded to 14 out of the 29 proposals received.

(c) and (d) Ministry of Power has made it obligatory on the part of State Governments to go in for competitive bidding and MOUs have not been allowed beyond 18.2.1995. The Ministry of Power has fixed a dead-line of 31st March, 1996 to all the proposals in the MOU/LOI etc. route for obtaining the 'in principle' clearance of CEA, failing which, the proposals will be put on the competitive bidding route.

देश में उच्च शक्ति और निम्नशक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना

1301. **श्री नागमणि:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यवार क्रमश: कितने उच्च शक्ति, निम्नशक्ति और बहुत ही निम्नशक्ति के ट्रांसमीटर तथा कितने ट्रान्पोंडर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ ट्रान्समीटर परियोजनाएं चालू होने के निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और ऐसी परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) यद्यपि आठवीं योजना (1.4.92 से 29.2.96 तक) के दौरान अभी तक भिन्न-भिन्न शक्तियों के 273 टी.वी. ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं तथापि, संलग्न विवरण में दिए गए राज्य वार ब्यौरों के अनुसार आठवीं योजना स्कीम के एक भाग के रूप में फिलहाल 345 ट्रांसमीटर परियोजनाएं विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वियनाधीन हैं। **(नीचे देखिए)**।

(ख) आठवीं योजना के लिए दूरदर्शन का अनुमोदित परिव्यय 2300 करोड़ रुपये है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांसमिशन सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं। तथापि धनराशि का राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) परियोजना स्थलों की दूरी तथा दुर्गम भू-भाग स्थितियों, आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति में देरी, टावरों के निर्माण में विलम्ब तथा सक्षम प्राधिकारी से नये सिरे से अनुमोदन लेने के लिए परियोजनाओं के लागत अनुमानों को संशोधित करने के लिए बाध्य करने वाली लागत वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों से मोकोकचुंग,